

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 667
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु सहनीय कृषि प्रौद्योगिकियों का विकास

667. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीर्घकालिक स्थिरता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि को जलवायु-सहनीय प्रणाली में रूपांतरित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता एवं चरम मौसम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु-सहनीय कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) सरकार दीर्घकालिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृषि को जलवायु-अनुकूल प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देकर खेत स्तर पर जल उपयोग की दक्षता बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने पर केंद्रित है ताकि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके। सॉइल हेल्थ एवं उर्वरता योजना रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देती है। समेकित बागवानी विकास मिशन कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूल के प्रति बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना सहित अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल खराब होने के कारण व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्ष 2011 से राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार (निक्रा) नामक एक परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। यह परियोजना अनियमित मानसून, चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का जिला स्तरीय आकलन और जलवायु परिवर्तन के भावी अनुमानों का आकलन करने के लिए एकीकृत सिमुलेशन मॉडलिंग अध्ययन किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनेल (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार, 651 प्रमुख कृषि प्रधान जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। इनमें से 310 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिनमें से 109 जिलों को 'अति संवेदनशील' और 201 जिलों को 'उच्च संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए, आईसीएआर ने विगत 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2900 किस्में जारी की हैं। इनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं।

कृषि पर प्रतिकूल मौसम के प्रभावों को कम करने के लिए, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के अंतर्गत, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर अगले 5 दिनों के लिए मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। आईएमडी द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमानों के साथ-साथ वर्षा और अन्य मौसम मापदंडों के आधार पर, 130 एग्रोमैट फील्ड यूनिट अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में कृषि मौसम संबंधी परामर्श तैयार करती हैं, जिन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, किसान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल ऐप 'मेघदूत' के माध्यम से अपने जिलों के लिए विशिष्ट मौसम संबंधी जानकारी, जिसमें अलर्ट और संबंधित कृषि मौसम संबंधी परामर्श शामिल हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो अंग्रेजी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। मौसम संबंधी जानकारी किसानों को आईएमडी के 'मौसम' ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है। पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी कई डिजिटल प्लेटफॉर्मों जैसे ईग्रामस्वराज (<https://egramswaraj.gov.in/>), पंचायती राज मंत्रालय का 'ग्राम मानचित्र' एप्लिकेशन (<https://grammanchitra.gov.in/gm4MVC>), 'मेरी पंचायत' मोबाइल ऐप और आईएमडी का मौसमग्राम वेब पोर्टल (<https://mausamgram.imd.gov.in/>) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
